

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1410

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

सीएसआर परियोजना पर व्यय

1410. श्री रिपुन बोरा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार गत तीन वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजना की कुल धनराशि खर्च करने में सफल रही है;
- (ख) यदि हां, तो सीएसआर व्यय के संबंध में संगठन-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न विकासपरक कार्यों के लिए स्थानीय सामाजिक संगठन, स्कूलों, अस्पतालों और स्थानीय निकायों का समर्थन कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार किए गए खर्च और इस संबंध में मानदंड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए निर्धारित रखते हैं। पिछले वर्ष का अव्ययित शेष, यदि कोई हो, तो उसे अगले वर्ष उस उद्देश्य के उपयोग के लिए आगे ले जाया जाता है जिसके लिए वह आवंटित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने चालू प्रतिबद्ध सीएसआर गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए हानि वाले वर्षों में भी सीएसआर निधि आवंटित की। गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

सीपीएसई का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	2905	2570	3118
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	853	960	1030
एनएमडीसी लि.	17418	16937	16724
मॉयल लि.	1143	962	929
एमएसटीसी लि.	80	215	200
मेकॉन लि.	67	49	17
केआईओसीएल लि.	38	16	33

(ग) और (घ): जी हाँ। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) विभिन्न विकास कार्यों/गतिविधियों के लिए स्थानीय सामाजिक संगठनों, स्कूलों, अस्पतालों और स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने का मानदंड यह है कि ये परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खानों की परिधि में परिचालित की जाती हैं। सीएसआर गतिविधियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनमें व्यय किया गया है उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के जरिए सतत आय अर्जन, दिव्यांगों को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ग्रामीण विकास, पर्यावरण अवलंबन, स्पोर्ट्स कोचिंग, परंपरागत कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना, इत्यादि शामिल हैं।

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1411

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

देश में नए इस्पात संयंत्र की स्थापना

1411. सुश्री सरोज पाण्डेय:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 से 2019 तक देश में कितने नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई और इन इस्पात संयंत्रों में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान किया गया; और
- (ख) इन संयंत्रों से इस्पात उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख): वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक देश में स्थापित नए इस्पात संयंत्रों के वर्ष वार आंकड़े, उनकी स्थापना के वर्ष से लेकर 2018-19 तक उनके औसत उत्पादन और उत्पादन में औसत परिवर्तन सहित नीचे दर्शाए गए हैं। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते, निजी इस्पात क्षेत्र में कार्मिकों की भर्ती संबंधी विशिष्ट निर्णय व्यक्तिगत इस्पात कंपनियों/निवेशकों द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर लिए जाते हैं।

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित इस्पात संयंत्रों की संख्या	निजी क्षेत्र में स्थापित इस्पात संयंत्रों की संख्या	कच्चे इस्पात उत्पादन का ब्यौरा (केवल नए स्थापित संयंत्र)	
			उत्पादन (औसत)	
			मात्रा (एमटी में)	औसत वृद्धि दर %
2013-14	शून्य	54	1.761	6.9
2014-15		66	3.696	-3.8
2015-16		20	1.025	-3.9
2016-17		50	4.778	44.0
2017-18		63	4.337	-0.5
2018-19*		84	4.333	-

स्रोत: जेपीसी; * अंतिम; एमटी=मिलियन टन

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1412

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात के निर्यात में गिरावट

1412. श्री माजीद मेमन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात के निर्यात में 34 प्रतिशत तक गिरावट आई है और तैयार इस्पात का आयात 4.7 प्रतिशत बढ़ा है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह भी सच है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से आयात बढ़ा है क्योंकि उन्होंने इस्पात की अतिरिक्त आपूर्ति भारत में भेज दी है; और
- (घ) सरकार ने बढ़ते इस्पात आयात को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): जी हाँ।

(ख): निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं:-

- i. यूएसए द्वारा इस्पात पर 25 प्रतिशत का एकतरफा टैरिफ लगाया जाना।
- ii. भारत के हित में निर्यात की जाने वाली कुछ इस्पात मदों पर ईयू और कनाडा द्वारा सुरक्षोपाय शुल्क लगाया जाना।
- iii. विश्व बाजार में इस्पात मूल्यों में कमी।
- iv. कुछ देशों का इस्पात निर्यात भारत की तरफ डायवर्ट होना।
- v. घरेलू स्तर पर उत्पादित न किए जाने वाले विशिष्ट इस्पात उत्पादों का आयात।
- vi. एफटीए सहयोगी देशों से आयात में वृद्धि।

(ग): दक्षिण कोरिया, जापान और इंडोनेशिया से आयात की मात्रा बढ़ी है जबकि चीन के मामले में यह घटी है।

(घ): सरकार ने मनमाने आयातों के खतरे से बचने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर एंटी-डंपिंग और प्रतिकारी शुल्क के रूप में व्यापारिक उपचारात्मक उपाय किए हैं।

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1413

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

रेलवे द्वारा इस्पात की मांग

1413. डा. कनवर दीप सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) रेल पटरियों के नवीनीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए भारतीय रेलवे की नई रेल लाइनों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राप्त मांग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने भारतीय रेलवे सहित, एजेंसियों को अपेक्षित मात्रा में इस्पात की पूर्ति करने के लिए कदम उठाए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): वर्ष 2019-20 में भारतीय रेलवे ने लगभग 17 लाख टन रेल की माँग की है। सेल 13.5 लाख टन रेल की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2016-17 से भारतीय रेलवे से प्राप्त भारी माँग और सेल द्वारा तदनुसार आपूर्ति का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

इकाई: हजार टन में

वर्ष	भारतीय रेलवे से प्राप्त भारी माँग	आपूर्ति
2016-17	1005	620
2017-18	1145	874
2018-19	1400	945
2019-20	1350	188 (अप्रैल-मई 2019)

(ग) और (घ): जी हाँ। भिलाई इस्पात संयंत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के तहत रेलवे की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए रेलों की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1.2 एमटीपीए क्षमता की यूनिवर्सल रेल मिल संस्थापित की है। यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) से उत्पादन नवंबर, 2016 से शुरू हो चुका है।
